मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97

महिला मित्र को अब बताया 'बहन'	3
बटला हाउस आजमगढ़ को ऐसे समझें....	4
कार्पोरेट खेती का एजेंडा बना मोदी सरकार का एजेंडा	5
विचार खिड़की : तीन महत्वपूर्ण लेख	6
हरियाणा में कोविड-19 के नाम पर खुली लूट	8

वर्ष 33 | अंक 46 | फरीदाबाद | 27 सितम्बर-3 अक्टूबर 2020 | फोन-8851091460 | ₹ 3.00

दुष्यंत चौटाला के विश्वासघात के बीच जेजेपी विधायक बगावत पर आमादा

कुछ विधायकों ने आलाकमान को नजरन्दाज कर किसान आंदोलन को दिया समर्थन

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: खेती-किसानी को बर्बाद करने वाले बिलों पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) में विधायकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले बयान दिया कि अगर एमएसपी नहीं रहेगी तो वो इस्तीफा दे देंगे। फिर इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार को इस बात के लिए बधाई दी कि उसने विभिन्न फसलों के रेट बढ़ा दिए। इसके बाद दुष्यंत ने कहा कि किसानों को तीनों अध्यादेशों पर बरगलाया गया। लेकिन खुद दुष्यंत की पार्टी जेजेपी में क्या हुआ?

जेजेपी के बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग और इसी पार्टी से शाहाबाद के विधायक रामकरण काला किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल हो गए। पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे रामकुमार गौतम और देवेंद्र सिंह बबली ने पहले ही किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया था। दस विधायकों की पार्टी में चार विधायक खुलकर किसानों के साथ हैं। कुछ और साथ आने वाले हैं लेकिन दुष्यंत अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है।

हाशिए पर जाती पार्टी

हरियाणा की किसान राजनीति में जेजेपी लगातार हाशिए की तरफ बढ़ रही है। इंडियन नैशनल लोकदल (इनेलो) से टूटकर 2019 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरी थी। हरियाणा के किसान बेल्ट में जेजेपी को ओमप्रकाश चौटाला के राजनीतिक रूप से नाकाम बेटों का पर्याय माना गया। जेजेपी ने बहुत तेजी से खट्टर सरकार पर दबाव बनाकर किसान विरोधी तीनों बिलों को वापस लेने को कहेगी।

हाथ से निकलते विधायक

चुनाव के बाद मौके का फायदा उठाते हुए जेजेपी ने जब कुर्सी के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया तो इसका सबसे पहला विरोध नारनौंद से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने किया। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गौतम ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देवेंद्र सिंह बबली ने विरोध का परचम बुलंद किया। लेकिन जिस तरह से दो अन्य विधायक जोगीराम सिहाग और रामकरण काला खुलकर किसानों के साथ धरने पर बैठे, उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि ये चारों विधायक पार्टी की लाइन से अलग चले गए हैं। इनके अलावा कम से कम दो और विधायक किसी भी समय इन चारों विधायकों के साथ खुलकर सामने आ सकते हैं। हाल ही में जेजेपी की जिस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अजय चौटाला को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था, उस बैठक में शामिल वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर दुष्यंत चौटाला ने अपना रवैया नहीं बदला तो यह पार्टी के हित में नहीं होगा।

जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हमने विधानसभा चुनावों में किसानों से वोट मांगा था। हमारी पूरी पार्टी का आधार किसान हैं। अब अगर किसानों पर ही आंच आ जाएगी और जेजेपी चुप रही तो फिर किसान किधर के रहेंगे। दुष्यंत को कुर्सी से इतना प्यार हो गया है कि वो पार्टी को भूलता जा रहा है।

फिलहाल सरकार को खतरा नहीं

जेजेपी के अंदर बढ़ती नाराजगी के बावजूद खट्टर सरकार के गिरने का कोई खतरा नहीं है। इसकी वजह है कांग्रेस का मजबूत न होना।

हालांकि हाल ही में इसे लेकर कयासबाजी शुरू हो गई थी कि अगर जेजेपी में असंतुष्ट बढ़ते हैं तो खट्टर सरकार गिर सकती है। कुछ विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात भी कही गई थी लेकिन जेजेपी के असंतुष्ट विधायक नाराज होने के बावजूद खट्टर सरकार को गिराना नहीं चाहते। क्योंकि कांग्रेस में नेतृत्व का मसला साफ नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं हैं और शैलजा या सुरजेवाला पर कोई कैसे दांव लगा सकता है।

दुष्यंत का पीआर दौरा

दुष्यंत ने किसान बेल्ट में पैदा हुई नाराजगी को दूर करने के लिए अचानक गांवों का दौरा शुरू कर दिया है। हालांकि जिन तमाम इलाकों में वो जा रहे हैं, वहां अधिकतर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके घर की महिलाएं होती हैं। जिनके फोटो दुष्यंत के साथ खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। खबर है कि तमाम इलाकों में दुष्यंत से वहां के युवकों ने पिछली सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजे जल्द से जल्द घोषित करने की अपील की। बहुत साफ है कि लोग तमाम मुद्दों पर हरियाणा की मौजूदा सरकार से बेहद नाराज हैं। उनका नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी राजनीतिक माना जा रहा है क्योंकि यहां से जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम ने पहले ही पार्टी में असंतुष्ट होने का बिगुल बजाया था। गौतम ने किसान आंदोलन का भी समर्थन कर दिया है। नारनौंद जाकर दुष्यंत यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असंतुष्ट विधायकों के इलाके में भी वो लोकप्रिय हैं।

उसकी जगह भी ले ली। लेकिन जब परीक्षा का मौका आया तो जेजेपी फेल हो गई। पीपली में किसानों पर सरेआम पुलिस और कुछ गुंडा तत्वों ने लाठियां बरसाईं। जेजेपी ने इसकी निन्दा करते हुए जांच की मांग की। इसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिस को लाठी चार्ज का न तो आदेश था और न ही उसने लाठीचार्ज किया, इसलिए जांच की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहले तो कहा कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं और बाद में बोले कि पुलिस ने आत्मरक्षा में ऐसा किया।

इन बयानों से साफ हो गया कि भाजपा पूरी तरह से अब जेजेपी के दबाव से मुक्त है। उसे जेजेपी की तरफ से सरकार गिराने का कोई खतरा नहीं है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक यह अंदाजा लगाए बैठे थे कि जेजेपी

किसान तो सड़कों पर उतरे लेकिन मज़दूर नदारद

किसानों एवं किसानी को बर्बाद करने के लिये मोदी सरकार द्वारा बनाये गये तीन कानूनों के विरुद्ध देश भर के किसान तो उग्र रूप धारण करके सड़कों पर उतर आये; लेकिन औद्योगिक मज़दूरों का गला घोंटने वाले हाल ही में बनाये गये काले कानूनों के विरुद्ध देश भर के किसी भी मज़दूर संगठन ने चूं तक नहीं की है।

सुधी पाठक बखूबी देख रहें होंगे कि मोदी सरकार अपने कॉर्पोरेट मित्रों के मुनाफ़े की हवस मिटाने के लिये किस तरह से खेती किसानी को-उनका निवाला बनाने जा रही है। संसद के इसी सत्र में औद्योगिक मज़दूरों के वैधानिक अधिकारों को छीनते हुये मोदी ने उन कारखानेदारों को, जिनके पास 300 तक मज़दूर काम करते हैं, अधिकार दिया है कि वे जब चाहें जैसे चाहें मज़दूरों की छटनी कर सकते हैं और चाहें तो कारखाना बंद भी कर सकते हैं।

लेकिन किसी भी कारखाने में मज़दूरों की सही संख्या मापने का कोई पुख्ता उपाय नही है वह अपने एक ही कारखाने में 300-300 मज़दूरों की एक से अधिक कितनी ही इकाइयां खोल सकता है, कोई पूछने वाला नहीं। इतना ही नहीं 400 मज़दूरों से काम लेने वाला यदि रजिस्टर में मात्र 300 ही दिखाये तो भी उसे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि जिसको पूछने का अधिकार सरकार ने दिया है वह लेबर महकमा पहले से ही बिका हुआ है। इतना सब भी मोदी को काफ़ी नहीं लगा तो उसने मज़दूरों द्वारा हड़ताल करने तक पर भी पाबंदी लगा दी। नये कानून में कहा गया है कि हड़ताल से पहले मज़दूरों को 14 दिन का नोटिस देना होगा। विदित है कि इस तरह के नोटिसों के जरिये हड़ताल व आंदोलन नहीं चला करते।

जिस किसान को ट्रेड यूनियन से जुड़े मज़दूरों की अपेक्षा असंगठित एवं अज्ञानी माना गया है, वह किसान तो आज पूरे जोर-शोर से सरकार से इस कदर जूझ रही है कि सरकार की चूलें हिल गई हैं। इसके विपरीत बड़े-बड़े बैनर व लंबे-चौड़े ट्रेड यूनियन के झंडे गाड़े व ऑफिस सजाये बैठे तमाम नेताओं को जैसे सांप सूंघ गया हो। असल मसला यह है कि आज मज़दूर नेता तो हैं लेकिन उनके साथ चलने वाले मज़दूर नहीं रह गये।

रतिया (सिरसा) में शुक्रवार को किसानों के आंदोलन में योगेन्द्र यादव भी शामिल हुए

कोरोना के बीच बिहार में चुनाव की तारीख घोषित

नई दिल्ली (म.मो.) बिहार में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का चुनाव 3 नवम्बर, तीसरे चरण का चुनाव 7 नवम्बर को होगा और 10 नवम्बर को नतीजे घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तारीख घोषित की।

कोरोना को देखते हुए यह चुनाव विशेष तरीके से होगा। हर मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या घटा दी गयी है। इसके अलावा तमाम तरह की शर्तें बिहार चुनाव को लेकर लगायी गयी हैं। जिसकी वजह से लोगों में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। आयोग की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ गयी है।